EDUZONE: International Peer Reviewed/Refereed Multidisciplinary Journal (EIPRMJ), ISSN: 2319-5045
Volume 13, Issue 1, January-June, 2024, Available online at: www.eduzonejournal.com

अनुच्छेद 370 हटने के पश्चात् कश्मीर के व्यावसायिक वातावरण में आये बदलाव के प्रभाव की समीक्षा

राकेश कुमार[1], डॉ. सोनिका[2]

[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक-124021

[2]सहायक प्राध्यापिका, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक-124021

----------**********----------

सार

किसी देश के व्यापारिक एवं व्यावसायिक वातावरण, उस देश में उत्पन्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अच्छे व्यापारिक वातावरण, अच्छी व्यापारिक संभावनाओं, अपेक्षाओं की संभावनाओं को दर्शाता है। इस व्यापारिक वातावरण में राजनैतिक सन्तुलन, करो में छूट, कार्यकुशल मानव संसाधन में खिंचाव, देश-विदेश निवेशकों के लिये आकर्षण इत्यादि। इस शोध पत्र में अनुच्छेद 370 के हटने के पश्चात् कश्मीर के व्यापारिक वातावरण में क्या-क्या परिवर्तन आये हैं, जिसके फलस्वरूप कश्मीर घाटी में क्या प्रभाव पड़ा है; समीक्षा की गई; जो कश्मीर घाटी के विकास के लिये एक अच्छी शुरूआत है। प्रस्तुत शोध पत्र में चार सालों में हुए बदलाव का अध्ययन किया है तथा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के पश्चात् वास्तविक व्यावसायिक विकास तथा जम्मू-कश्मीर की उन्नति, आर्थिक विकास तथा रोजगारपरक उपयोगी विकास का अध्ययन किया गया है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के पश्चात् यह वापिस से अपनी वास्तविक पटरी पर स्वर्ग की भूमिका का निर्वाह करने लगा है।

कुंजी शब्द: व्यापारिक वातावरण, सम्भावनाऐं, मानव संसाधन, परिवर्तन, क्षेत्रीय विकास।

परिचय

भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् कश्मीर घाटी की राजनैतिक तथा सामरिक दृष्टिकोण को दृष्टि में रखते हुए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 लगाई गई थी। इस अनुच्छेद का कश्मीर के अस्तित्व के लिए लाभ कम तथा हानियाँ अधिक मात्रा में हो रही थीं इस अनुच्छेद का समयबद्ध समीक्षा की गई; परन्तु घाटी के नेताओं के राजनैतिक की सही रिर्पोट; लोगों के सम्मुख कभी आई ही नहीं। कश्मीर की इस नीति से, जो त्रासदी कश्मीर के लोगों, विशेषकर कश्मीरी पंडितों को झेलनी पड़ी; उस का परिदृश्य पूरे देश में किसी से छिपा नहीं है। (एजाज वानी, 2022)

व्यवसाय को राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक एवं प्रौद्योगिक तथा संगठन के संसाधन के घटकों पर निर्भर करता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक गतिविधियों में कश्मीर घाटी में दशकों से एक दम विपरित वातावरण रहा है; जिसके फलस्वरूप कश्मीर घाटी में इस क्षेत्रों में अच्छी संभावना होते हुए भी देश के अन्य भागों की अपेक्षा पिछड़ता चला गया है। इसलिए यह 370 अनुच्छेद हटने के पश्चात् जम्मू एवं

कश्मीर में एक अनुरूप व्यवसायिक वातावरण पुनः स्थापित होने के सकारात्मक संकेत मिले हैं। ये संकेत कश्मीर की रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर में एक व्यापक आर्थिक सुधार की एक अच्छी अपेक्षा की जा सकती है। (**Economic Survey Report of Kashmir :** 2022-23)

कश्मीर का बदलता आर्थिक स्वरूप

भारतीय संविधान की अनुच्छेद 370 हटने के पश्चात् संभावित व्यवसायिक वातावरण के परिवर्तन के व्यापक संकेत पिछले दो वर्षों में मिलने प्रारम्भ हो गये हैं। कश्मीर के बदलते व्यवसायिक वातावरण को लेकर कश्मीर की आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर में लघु उद्योग की अपार संभावनाएँ हैं। इसके अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर की व्यापार एवं निर्यात नीति 2018-28 रिपोर्ट के अनुसार सम्पूर्ण कश्मीर घाटी में अपार संभावनाऐं है। इस रिपोर्ट के अनुसार व्यापार की उदारीकरण नीति के अनुसार घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप में सम्भावऐं हैं, अगर व्यापार सम्बन्धी सभी रूकावटों को दूर किया जाये। इस रिपोर्ट में 10 वर्षों से लेकर, व्यापारिक रूख में व्यापक रूप से बदलाव आने की सम्भावना है, जिसके फलस्वरूप रोजगार में भी कई गुणा वृद्धि होने की भविष्यवाणी की गई है। (**Reort of Department of Industries and Commerce, Govt. of J & K,** 2018)

अनुच्छेद 370 हटने के पश्चात् कश्मीर सरकार ने व्यापारिक दृष्टिकोण को बहुआयामी विकास के दृष्टिकोण से समीक्षा की है। इस दृष्टिकोण का **SWOT Analysis** किया गया है, जिसके फलस्वरूप व्यापार गुरूओं (**Business Expert**) द्वारा कश्मीर घाटी में दुर्बल बिन्दुओं को शक्ति बिन्दुओं में परिवर्तन करने के कारगर सुझाव दिए गए हैं, ताकि भविष्य में व्यापारिक दृष्टि से कश्मीर निरन्तर अग्रसर हो सके। आगे व्यापार गुरूओं द्वारा व्यापार में अन्तराल समीक्षा (**Gap Assessment**) का भी समयबद्ध मूल्यांकन किया गया है, ताकि भविष्य में व्यापारिक तेजी एवं मंदी का सही अनुमान लगाया जा सके। इसके लिए आज भी निरन्तर प्रयत्न जारी है। (दानिस यूसुफ, 2021)

मार्च माह में कश्मीर में प्रथम विदेशी निवेश दुबई के अमीर समूह द्वारा 60 मिलियन अमेरीकी डालर का निवेश हुआ है। इस निवेश में श्रीनगर में व्यापारिक माल का निर्माण किया जायेगा। (राइटर, मार्च 2023) इसके अतिरिक्त जम्मू एवं कश्मीर सरकार के अनुसार भविष्य में 75000 करोड रूपये का विदेशी निवेश आने की पूरी संभावना है। मार्च माह में ही जम्मू-कश्मीर की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत 2200 करोड़ के निवेश से 10000 नौकरियों के उत्पन्न होने की संभावना प्रकट की है। (जम्मू-कश्मीर की नवीन औद्योगिक नीति, 2021)

औद्योगिक विकास में अनुच्छेद 370 बहुत बड़ी रूकावट थी। इस सन्दर्भ में जम्मू-कश्मीर की औद्योगिक नीति के अनुसार कश्मीर की युवा जनसंख्या के विकास के लिए, नये अवसर उत्पन्न होने की पूर्ण सम्भावना है। (जम्मू एवं कश्मीर की नई औद्योगिक नीति, 2021) सन् 2021-22 में जम्मू व कश्मीर में 310 कम्पनियाँ स्थापित हुई हैं। ये कम्पनियाँ 175 औद्योगिक इकाईया 2021 में स्थापित हुई। इसके अतिरिक्त सन् 2022-23 में 1074 औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई तथा आगामी दो वर्षों में 66000 करोड़ का निवेश जम्मू एवं कश्मीर के विभिन्न जिलों में निजी क्षेत्र में आने की संभावना है। (शाहबाज सुल्तान, 2022) जम्मू-कश्मीर के भविष्य में आर्थिक सुधार की दृष्टि से जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 व 35ए के हटने के पश्चात् बाहरी राज्यों के निवासियों को 185 औद्योगिक इकाईयों को स्थापित करने के लिए प्लाट उपलब्ध कराये गए हैं। (**Express News Service,** 2023) व्यवसायिक वातावरण के आधार पर

व्यापार से जुड़े कारकों को गतिशील बनाने के लिए घाटी में उग्रवाद की घटनाओं में व्यापक कमी, बहुउद्देशीय पारदर्शिता, प्रशासन की जवाबदेही, व्यापारियों तथा सरकारी अधिकारियों में सही तालमेल, एक संतुलित व्यवसायिक वातावरण का सूचक है। ये सभी गुणात्मक सूचक में व्यापक वृद्धि, अनुच्छेद 370 व 35ए के हटने के बाद ही उत्पन्न हो सका है। (शाहबाज़ सुल्तान, 2022)

इस संवैधानिक अनुच्छेद 370 के हटने से ही व्यापार तथा व्यापारियों में परस्पर निर्भरता में वृद्धि हुई है। व्यवसाय तथा व्यापारियों की अपेक्षाकृत गतिशीलता आई है। इस अनुच्छेद के इन चार वर्षों के अन्तराल में आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन, घाटी में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।

व्यवासायिक घटकों में निरन्तर परिवर्तन के परिणास्वरूप व्यवसाय के उद्देश्य, योजना एवं नीतियों में भी व्यापक परिवर्तन आया है, जो एक-दूसरे के पूरक बने हैं, जो एक सकारात्मक व्यापारिक तथा व्यावसायिक वातावरण को स्थाई रूप से स्थापित करने में निरन्तर सहायक सिद्ध हो सकेगा। (शाहबाज सुल्तान, 2019)

विषम दशाऐं एवं व्यवसायिक अनुकूलता

अनुच्छेद 370 व 35ए के हटाने से विषम दशाऐं व व्यवसायिक अनुकलूता में व्यापक स्तर पर वृद्धि हुई है। व्यापार तथा व्यवसाय में आने वाली रूकावटों का सुगमतापूर्ण हल निकाला जा सकेगा, जो पहले उद्यमियों को बड़े कठिन दौर से गुजरना पड़ता था। इस सन्दर्भ में सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों ने व्यापारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न औद्योगिक स्थलों पर ही उपलब्ध कराए गए हैं। पर्यटन उद्योग जो उग्रवाद के कारण उजड़ चुका था, अब कई गुणा वृद्धि का आगमन हुआ है।

यह अच्छे व्यवसायिक वातावरण में व्यापक परिवर्तन के कारण ही बन पड़ा है। पिछले मई 2023 आंकड़ों के अनुसार कश्मीर घाटी में 1.70 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ, जो एक रिकार्ड है।

इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जी-20 का श्रीनगर में आयोजन और अब मिस वर्ल्ड का आयोजन कश्मीर में करना एक सन्तुलित व्यवसायिक वातावरण के उत्पन्न होने का प्रतीक है, जो आगामी अपार व्यापारिक तथा व्यवसायिक सम्भावनाओं का कश्मीर के लिए आगामी वर्षों में एक वरदान सिद्ध होगा, ऐसा अपेक्षित है।

निष्कर्ष

किसी देश अथवा प्रान्त के व्यापारिक, औद्योगिक प्रगति के लिए व्यावसायिक वातावरण का सौहार्दपूर्ण होना अति आवश्यक है। यह व्यवसायिक वातावरण, अनुच्छेद 370 व 35ए के हटने के बाद, घरेलू तथा विदेशी निवेशकों का बहुत अच्छा रूझान हुआ है, जो कश्मीर की आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन के लिए अति आवश्यक था। इन धराओ के हटने से उद्योगों विशेषकर पर्यटन उद्योग में पिछले 4 वर्षों में व्यापक तौर पर वृद्धि हुई है।

यह सभी इन दोनों अनुच्छेदों के हटने से ही एक अच्छे औद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरण का उत्पन्न होने का स्वप्न पूर्ण हो सका है। इन अनुच्छेदों के हटने से ही घाटी में संतुलित रूप से प्रादेशिक आधारभूत विकसित हो सकेगा, जो प्रादेशिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कश्मीर के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भी संतुलित रूप से विकास हो सकेगा।

सन्दर्भ सूची

[1]. प्रदीप कुमार **कौशिक** (2019), "अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू एवं **कश्मीर** में **निवेश** की संभावनाएँ, अगस्त 13, 2019, SSRN Product & Services (**शाहबाज** सुल्तान, 2022)

[2]. **कश्मीर** में लघु–उद्योगों की अपार संभावनएँ एक दृश्टिकोण, Journal of XI Shiyou University, Natural Science Edition, Vol. 18, Issue 7, July 2022, pp. 437-452.

[3]. गोविंद यूसूफ (2007), जम्मू– **कश्मीर** में एलओसी संयुक्त प्रयत्न से आर्थिक विकास की संभावनाएँ, Vol. 5, No. 1, July 2007, Pugwas, Journal Published by Pugwash Confroucesion Science and World Affairs Nobal Peace Prizes, 1995.

[4]. आरिफ कमाल एवं दिपांकर सैन गुप्ता (2013), जम्मू एवं **कश्मीर** में आर्थिक पुनःजागरण : एक सम्भावना, JSTOR Conciliation Resources, Burghley Road, London.

[5]. आरिफ गुलज़ार एवं तनवर अहमद खान (2019), **कश्मीर** के पर्यटन उद्योग पर आर्थिक प्रभाव का **विश्लेषण**, Vol. 23, No. 3 (July-September, 2019), pp. 108-17, published by Kapoor Surya Foundation.

[6]. ऐजाजवानी (2022), **कश्मीर** के पुनः उत्थान के लिए एक आधारभूत की अत्यन्त **आवश्यकता**, ORF Observer Research Foundation, April 23, 2022.

[7]. Economic Survey Report of 2022-23 of Kashmir.

[8]. **दानिश युसूफ** (2021), **कश्मीर** की अर्थव्यवस्था : एक समकालीन दृश्टिकोण, CLAWS Centre for Land Warfare Studies, September 20, 2021.